[2014] 10 एस.सी.आर 397

के. के. दीक्षित और अन्य

बनाम

राजस्थान आवासनन मंडल और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8479-8482/2014)

05 सितंबर, 2014

[फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और शिव कीर्ति सिंह, जे.जे.]

सेवा कानूनः

वरिष्ठता सूची – डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के लिए उनके संबंधित नियतांश में पदोन्नति के उद्देश्य से दो अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार करना - अभिनिर्धारितः मंडल वैध रूप से डिग्री धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) और डिप्लोमा धारकों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार कर सकता है - - हालाँकि, ऐसी पात्रता सूची को वरिष्ठता सूची समझने की भूल नहीं की जा सकती जो भर्ती के लिए चयन के समय मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर सामान्य रहना चाहिए - राजस्थान आवासनन मंडल मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति की शर्तें विनियम, 1976।

पदोन्नति - वरिष्ठता सूची - डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर इंजीनियरों के बीच विवाद - 'एएमआईई' की डिग्री/योग्यता प्राप्त करने पर डिप्लोमा धारक परियोजना इंजीनियर्स (जूनियर) को पद पर पदोन्नति के लिए सेवा के 3 साल के कुल अनुभव की पात्रता के उद्देश्य से ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले सेवा के अपने अनुभव को गिनने

का अधिकार। डिग्री धारकों के लिए निर्धारित नियतांश में परियोजना इंजीनियर (सीनियर)। - अभिनिर्धारित: योग्य नहीं - ऐसे नियतांश के तहत पदोन्नति का दावा करने के लिए एएमआईई की योग्यता/डिग्री प्राप्त करने के बाद 3 साल की सेवा का अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए।

आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. प्रारंभ में केवल डिप्लोमा धारकों को ही परियोजना इंजीनियर (जूनियर) के पद पर विनियमों के तहत नियुक्त किया जाता था और उनके एएमआईई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर सेवा में रहते हुए उन्हें 3:7 के अनुपात में डिप्लोमा धारकों के रूप में उनकी पिछली सेवा का लाभ दिया जाना था। यानी, पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से एएमआईई के साथ उनकी 3 साल की सेवा को डिप्लोमा धारक के रूप में 7 साल की सेवा के रूप में माना गया था। निर्धारित अनुपात में पिछली सेवा का यह लाभ मंडल के दिनांक 17.4.1979 के एक संकल्प के कारण था। जो दर्ज करता है कि एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डिप्लोमा धारक इंजीनियरों को डिग्री धारकों की सूची में सबसे नीचे रखने की वर्तमान प्रथा उचित है। खंड (9)(ए) जो अनुसूची तकनीकी के साथ पढ़ने पर पदोन्नति का प्रावधान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उच्च पद पर पहली पदोन्नति के संबंध में, यानी, परियोजना अभियंता (जूनियर) के पद से परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति }, पात्र व्यक्ति की पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जानी आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने सही माना है कि परियोजना इंजीनियर (जूनियर) के कैडर को केवल वरिष्ठता के उद्देश्य से विभाजित नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि परियोजना इंजीनियर (सीनियर) के कैडर में पदोन्नति के लिए 20% नियतांश का प्रावधान है। डिग्री धारकों के लिए और डिप्लोमा धारकों के लिए 30% नियतांश। उच्च न्यायालय के व्यावहारिक दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि मंडल वैध

रूप से डिग्री धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) और डिप्लोमा धारकों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार कर सकता है। ऐसी पात्रता सूची को वरिष्ठता सूची समझने की भूल नहीं की जा सकती है, जो भर्ती के लिए चयन के समय मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर सामान्य बनी रहनी चाहिए। यदि चयन प्रक्रिया अलग होती तो ही अलग वरिष्ठता सूची के लिए बहस की कोई गुंजाइश होती। प्रारंभिक चयन के समय योग्यता के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रारंभिक वरिष्ठता और नियमित नियुक्ति की तिथि में परिवर्तन के लिए किसी कानूनी शर्त के अभाव में, वरिष्ठता सूची में केवल इसलिए बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ डिप्लोमा धारक परियोजना इंजीनियर्स (जूनियर) ने एक डिग्री के बराबर एएमआईई की योग्यता हासिल कर ली है। तीन साल या सात साल की सेवा का अनुभव क्रमशः डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों को पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में अपना नाम शामिल करने का अधिकार देगा ताकि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए विभिन्न नियतांश के प्रावधान को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके।[पैरा 8,19][405-ई-जी; 411-बी-एच]

2. तीन साल के सेवा अनुभव के साथ डिग्री और सात साल के सेवा अनुभव के साथ डिप्लोमा अपने आप में एक डिग्री धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा और एक डिप्लोमा धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा में गुणात्मक अंतर को इंगित करता है। प्रासंगिक विनियमन किसी डिप्लोमा धारक के लिए पदोन्नति के लिए किसी भी कम कुल अनुभव पर विचार नहीं करता है जो सेवा में रहते हुए डिग्री या एएमआईई योग्यता प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में तीन साल की सेवा के अनुभव वाले डिग्री धारकों के लिए नियतांश के वॉटर-टाइट डिब्बे में प्रवेश करने के लिए, एएमआईई योग्यता वाले डिप्लोमा धारक को यह दिखाना होगा कि वह संपूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करता है। यानी, वह एक डिग्री धारक है और उसके पास डिग्री धारक के रूप में तीन साल की सेवा का अनुभव है। 'सेवा का अनुभव' शब्द से पहले आने वाले 'कुल'

शब्द का अर्थ डिप्लोमा धारक या डिग्री धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा से नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी मामले में एक डिप्लोमा धारक को पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए सात साल की सेवा का अनुभव होना आवश्यक है और इसलिए उपरोक्त संदर्भ में 'कुल' शब्द अप्रयुक्त या अनावश्यक होगा। [पैरा 29 से 31] [421-एफएच; 422-ए, डी-जी; 423-डी]

3. डिप्लोमा के आधार पर भर्ती किए गए परियोजना इंजीनियर (जूनियर) 'एएमआईई' की योग्यता प्राप्त करने पर, पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले सेवा के अपने अनुभव को गिनने के हकदार नहीं हैं। डिग्री धारक परियोजना इंजीनियर्स (जूनियर) की पदोन्नति के लिए निर्धारित नियतांश के विरुद्ध परियोजना इंजीनियर (सीनियर)। ऐसे 20% नियतांश के विरुद्ध पदोन्नति का दावा करने के लिए एएमआईई की योग्यता या डिग्री प्राप्त करने के बाद सेवा का तीन साल का अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए। [पैरा 34, 35) [425-बी-सी]

शैलेंद्र दानिया बनाम एस.पी. दुबे (2007) 5 एससीसी 535: 2007 (5) एससीआर 190- पर निर्भरता।

एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 पूरक (1) एससीसी 584: 1991 (2) पूरक एससीआर 423; भारतीय एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य बनाम एस. गोपालकृष्णन (2001) 2 एससीसी 362 : 2000 (5) पूरक एससीआर 548; चल्ला जया भास्कर और अन्य बनाम थुंगथुर्ती सुरेंदर और अन्य (2010) 13 एससीसी 328: 2010 (13) एससीआर 643; चंद्रवती पी.के. और अन्य बनाम सी.के.साजी और अन्य (2004) 3 एससीसी 734: 2004 (2) एससीआर 330; विजय सिंह देवड़ा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 3 एससीसी 118: 1996 (7) पूरक एससीआर 170; अनिल कुमार गुप्ता और अन्य बनाम नगरपालिका दिल्ली निगम और अन्य (2000) 1 एससीसी 128: 1999 (4) पूरक

एससीआर 553; एम.बी.जोशी और अन्य आदि बनाम सतीश कुमार पांडे और अन्य आदि 1993 पूरक (2) एससीसी 419: 1992 (2) पूरक एससीआर 1; ए.के.रघुमनी सिंह और अन्य बनाम गोपाल चंद्र नाथ और अन्य (2000) 4 एससीसी 30: 2000 (2) एससीआर 943; चंद अदलखा और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य। 1989 (1) पूरक एससीसी 116: 1988 (3) पूरक एससीआर 253; डी.स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 4 एससीसी 753: 1997 (3) एससीआर 1040 -संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भः

2007 (5) एससीआर 190	भरोसा किया	पैरा 21
1991 (2) पूरक एससीआर 423	संदर्भित	पैरा 21
2000 (5) पूरक एससीआर 548	संदर्भित	पैरा 21
2010 (13) एससीआर 643	संदर्भित	पैरा 21
2004 (2) एससीआर 330	संदर्भित	पैरा 21
1996 (7) पूरक एससीआर 170	संदर्भित	पैरा 21
1999 (4) पूरक एससीआर 553	संदर्भित	पैरा 22
1992 (2) पूरक एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 22
2000 (2) एससीआर 943	संदर्भित	पैरा 22
1988 (3) पूरक एससीआर 253	संदर्भित	पैरा 22
1997 (3) एससीआर 1040	संदर्भित	पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8479-8482/2014

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील (सिविल) संख्या 64/1993, डी.बी.स्पेशल अपील (सिविल) संख्या 67/1993, डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7063/1993 और डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20/1993 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.05.2007 से उत्पन्न।

संजीव प्रकाश शर्मा, शोभा, ज्योति राणा, प्रसन्ना, मोहन, अंबिका बेदी, पीयूष जैन, अंकित सेठी, रवींद्र बना, अपीलार्थियों की ओर से।

विजय हंसारिया, बद्री दास शर्मा, नरोत्तम व्यास, सतीश चन्द वर्मा, वेद पर्य्या, मनु मृदुल, अभिजीत सेनगुप्ता, एकता राय, अनीश कुमार गुप्ता, दीप शिखा भारती, आर. डी. गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, प्रवीण चतुर्वेदी, एम. एल. लाहोटी, रश्मि सिंघानिया, गार्गी बी. भारती, सारद कुमार सिंघानिया, मिलिंद कुमार, प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

शिवा कीर्ति सिंह, न्यायाधिपति.

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. ये अपीलें उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा तय की गई सेवा मामलों की लंबी सूची में अतिरिक्त हैं जो आगे की पदोन्नति के लिए पात्रता के मामले में "डिप्लोमा धारक" और "डिग्री धारक" इंजीनियरों के बीच विवादों को हल करती हैं। सभी अपीलार्थी राजस्थान आवासन मंडल की सेवा में परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के रूप में नियुक्त डिग्री धारक अभियंताओं की श्रेणी से संबंधित थे (संक्षिप्तता के लिए जिसे 'मंडल' के रूप में संदर्भित किया जाता है)। लड़ने वाले प्रतिवादी के पास भी वही पद था

लेकिन शुरू में केवल डिप्लोमा धारक के रूप में जिन्होंने बाद में एएमआईई की योग्यता प्राप्त की जो इंजीनियरिंग में डिग्री के बराबर है।

3. चूँकि सभी अपीलें जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं और तथ्यों के साथ-साथ कानून के मुद्दे भी समान हैं, इसलिए सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

4. सर्वप्रथम, इन अपीलों में कानून के प्रश्नों के माध्यम से उठाए गए दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि तथ्यों और कानून की बाद की चर्चा विवाद में दोनों मुद्दों/प्रश्नों का उत्तर देने में मदद कर सके। मुद्दे इस प्रकार हैंः

> (i) क्या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि डिप्लोमा धारक परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) 'एएमआईई' की डिग्री/योग्यता प्राप्त करने पर डिग्री धारकों के लिए निर्धारित नियतांश में परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति के लिए 3 साल के कुल सेवा अनुभव की पात्रता के उद्देश्य से ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले अपने सेवा अनुभव को गिनने के हकदार होंगे?
>
> ((ii) क्या खण्ड पीठ ने अपने-अपने नियतांश में पदोन्नति के उद्देश्य से डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के लिए दो अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश को अपास्त करने में गलती की है?

5. राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंडल ने राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति

की शर्तें विनियम, 1976 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) बनाए। विनियमों के अध्याय 2 में खंड (6) से (10) शामिल हैं जो भर्ती और पदोन्नति की शर्तों का प्रावधान करते हैं। खंड (6) समय-समय पर बनाए गए पदों को भरने का तरीका प्रदान करता है। प्रतिनियुक्ति पर मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों के अवशोषण के संदर्भ में, 'श्रेणी' शब्द का उपयोग बनाए गए और खाली पदों के संदर्भ में किया गया है। खंड (7) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

> "(7) मंडल की सेवा में कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात और विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव इन विनियमों में संलग्न 'अनुसूची' के अनुसार होगा।"

विनियमों का खंड (9)(ए) पदोन्नति से संबंधित है और निम्नानुसार प्रावधान करता हैः

> "(9)(ए) पदोन्नति
>
> उच्च पद पर प्रथम पदोन्नति के संबंध में, योग्य व्यक्ति की पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी। द्वितीय पदोन्नति 50:50 की पदोन्नति में योग्यता एवं वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी।"

खंड (9) (बी) में प्रावधान है कि "प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता सूचियां तैयार की जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।" खंड (10) 'वरिष्ठता' से संबंधित है और इस प्रकार हैः

> "(10) वरिष्ठताः

एक ही वर्ष में भर्ती किए गए व्यक्तियों में से, पदोन्नत व्यक्ति उन लोगों से वरिष्ठ होंगे जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पदोन्नत होने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर रैंक के साथ नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठता को उचित सम्मान देते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए लोगों की पारस्परिक वरिष्ठता निचले कैडर में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के अनुसार होगी।"

6. विनियमों के अध्याय 3 में विविध प्रावधान हैं और इसमें खंड (12) शामिल है जो मंडल को उन सामान्य निर्देशों को जारी करने का अधिकार देता है जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं ताकि उन संदेह, कमियों, विसंगति या विसंगतियों को दूर किया जा सके जो विनियमों की व्याख्या करने या उन्हें प्रभावी बनाने या उन्हें लागू करने में उत्पन्न हो सकते हैं। विनियमों में परिशिष्ट के रूप में विभिन्न अनुसूचियाँ शामिल हैं। हस्तगत मामले में अकेले "अनुसूची तकनीकी" का महत्व है और यह प्रवेश स्तर पर परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद को दर्शाता है। इस पद को 97 प्रतिशत सीधी भर्ती और 3 प्रतिशत मंडल कर्मचारियों द्वारा भरा जाना है। आवश्यक मूल योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है। पदानुक्रम में अगला पद, जिसमें पदोन्नति जारी है, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) है। इस पद के लिए भर्ती का स्रोत 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 20 प्रतिशत डिग्री धारक की पदोन्नति और 30 प्रतिशत डिप्लोमा धारक की पदोन्नति है। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए, आवश्यक योग्यता भवन के डिजाइन और निर्माण में कम से कम एक वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है। परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों के लिए अनुसूची तकनीकी के कॉलम 6 में निर्धारित न्यूनतम अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती

है। चूंकि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी ने पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव और योग्यता निर्धारित करने वाले कई शब्दों पर बहुत जोर दिया है, इसलिए प्रासंगिक कॉलम संख्या 6 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

> "यह पद उन पी.ई.जूनियरों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा जो तीन वर्ष की सेवा के कुल अनुभव के साथ डिग्री धारक हैं।
>
> यह पद पी.ई.जूनियर से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा जो 7 वर्ष की सेवा के कुल अनुभव के साथ डिप्लोमा धारक हैं। (137.20)
>
> सरकार द्वारा अनुमोदन दिनांक 25.2.2000 लागू 9.12.87
>
> या
>
> सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के समकक्ष होने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता।"

7. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद के ऊपर पदानुक्रम में चार उच्च पद हैं। उन सभी को केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है और परियोजना इंजीनियर (वरिष्ठ) के ठीक ऊपर रेजिडेंट इंजीनियर के पद को छोड़कर सिविल में इंजीनियरिंग में डिग्री की आवश्यकता होती है, जिसके लिए "योग्य परियोजना इंजीनियर (वरिष्ठ) को पदोन्नति देकर डिग्री धारक द्वारा 75 प्रतिशत और डिप्लोमा धारक द्वारा 25 प्रतिशत" भरने की आवश्यकता होती है। अनुसूची तकनीकी का कॉलम 6 रेजिडेंट इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव और योग्यता प्रदान करता है (i) 5 साल के अनुभव के साथ डिग्री धारक और (ii) 13 साल के अनुभव के साथ डिप्लोमा धारक। एक डिप्लोमा धारक, जैसा कि पहले देखा गया है, आगे किसी भी पदोन्नति के लिए योग्य नहीं है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि शुरू में केवल डिप्लोमा धारकों को परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद के लिए विनियमों के तहत नियुक्त किया गया था और सेवा में रहते हुए एएमआईई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उन्हें 3:7 के अनुपात में डिप्लोमा धारकों के रूप में उनकी पिछली सेवा का लाभ दिया जाना था, यानी एएमआईई के साथ उनकी 3 साल की सेवा को पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से डिप्लोमा धारक के रूप में 7 साल की सेवा के रूप में माना जाता था। निर्धारित अनुपात में पिछली सेवा का यह लाभ मंडल के दिनांकित 17.4.1979 के एक प्रस्ताव के कारण था, जिसमें लिखा है कि "एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डिप्लोमा धारक इंजीनियरों को डिग्री धारकों की सूची में सबसे नीचे रखने की वर्तमान प्रथा उचित है। लेकिन यह भी निर्णय लिया गया है कि उनका अनुभव 3:7 (3 वर्ष के डिग्री धारक 7 वर्ष के डिप्लोमा धारकों के बराबर) के अनुपात में निर्धारक होना चाहिए। कुछ डिप्लोमा धारक जिन्हें शुरू में विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें न केवल मंडल द्वारा आदेश दिनांक 18.5.1987 के अनुसार नियमित किया गया था, बल्कि उन्हें नियमित रूप से नियुक्त डिप्लोमा धारकों की तरह उनकी पिछली सेवा का लाभ भी दिया गया था और बाद की श्रेणी के साथ उन्होंने वर्ष 1992 में परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर तदर्थ पदोन्नति भी प्राप्त की। इस बीच, मंडल द्वारा जारी मार्च 1988 के एक विज्ञापन के अनुसार, डिग्री धारकों के रूप में अपीलार्थियों ने आवेदन किया और चयन पर, 18.3.1989 को परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर नियुक्त किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्लोमा, एएमआईई और डिग्री धारकों सहित परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की एक सामान्य अनंतिम वरिष्ठता सूची 11.8.1989 को जारी की गई थी और हालाँकि अपीलार्थियों ने उक्त वरिष्ठता सूची पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मंडल द्वारा जनवरी और फरवरी 1992 में तदर्थ आधार पर कुछ डिप्लोमा धारकों को पदोन्नति दी गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

9. अपीलार्थी- के.के.दीक्षित और कुछ अन्य लोगों ने मंडल के संकल्प दिनांक 17.4.1979, संयुक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 11.8.1989 और एएमआईई के साथ डिप्लोमा धारकों की तदर्थ पदोन्नति को चुनौती देते हुए रिट याचिका को प्राथमिकता दी। रिट याचिका को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 7.7.1993 को केवल अनुभव की गिनती से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद स्वीकार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल ऐसी सेवा को पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए गिना जा सकता है जो नियमितकरण के बाद तदर्थ परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) द्वारा प्रदान की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि तदर्थ नियुक्तियों के रूप में उनके अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

10. रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में उठाई गई अन्य दो शिकायतों पर निर्णय पारित करने का अनुरोध करते हुए एक पुनर्विलोकन याचिका को प्राथमिकता दी। पहली शिकायत यह थी कि परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों की वरिष्ठता सूची अलग से तैयार की जानी चाहिए। दूसरी शिकायत यह थी कि संकल्प संख्या 6 दिनांक 17.4.1979 को ध्यान में रखते हुए उन डिप्लोमा धारकों को, जिन्होंने सेवा में रहते हुए एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उस वर्ष के डिग्री धारकों से नीचे रखा जाना चाहिए। उपरोक्त दावे या शिकायतें दोनों इस दलील पर आधारित थीं कि भर्ती नियमों के अनुसार डिग्री धारकों के लिए अलग नियतांश है और डिप्लोमा धारकों के लिए भी अलग नियतांश है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.9.1993 के आदेश द्वारा पुनर्विलोकन याचिका को इस हद तक स्वीकार किया कि मंडल डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार करेगा परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) और ऐसे परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) जिन्होंने सेवा में रहते हुए एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उस वर्ष डिग्री धारक परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

11. रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.1993 से और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.9.1993 से व्यथित, कुछ प्रभावित डिप्लोमा धारकों ने क्रमशः डी.बी.विशेष अपील (सी) 67/1993 और 64/1993 को प्राथमिकता दी। डी. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20/1993 और 7063/1993 सहित पाँच अन्य मामलों को भी विशेष अपीलों के साथ जोड़ा गया था। परियोजना इंजीनियर (जूनियर) के पद पर डिग्री धारकों के रूप में मंडल की सेवा में प्रवेश करने वालों द्वारा पसंद की जाने वाली इन अपीलों में चुनौती के तहत दिनांकित 25.5.2007 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उन्हें एक साथ सुना गया और आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। चूँकि ये अपीलें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा तय किए गए सात मामलों में से केवल चार से उत्पन्न होती हैं, इसलिए शेष तीन मामलों का विवरण इंगित करना आवश्यक नहीं है जिन्हें अपील के तहत सामान्य आदेश द्वारा भी निस्तारित किया गया था।

12. अपील के तहत निर्णय से, उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद के तहत तीन प्रश्नों का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने तीन प्रश्नों का सारांश इस प्रकार दिया हैः

> "1. क्या परियोजना इंजीनियर (जूनियर) जिन्हें प्रारंभ में तदर्थ/स्थानापन्न/अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती और पदोन्नति की शर्तें विनियम, 1976 के 'अनुसूची तकनीकी' के नीचे नोट के खंड 3 के संदर्भ में जांच करने और सेवा का सदस्य बनाये जाने पर परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति की पात्रता के लिए वरिष्ठता और अनुभव के उद्देश्य से उस क्षमता में प्रदान की गई सेवा की अवधि को गिनने के हकदार हैं, जैसा कि 1976 के विनियमों की

'अनुसूची तकनीकी' में क्रम संख्या 2 के कॉलम संख्या 6 में प्रदान किया गया है?

2. क्या डिप्लोमा के आधार पर भर्ती किए गए परियोजना अभियंता (कनिष्ठ), 'एएमआईई' की योग्यता प्राप्त करने पर, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति के लिए 'तीन साल के कुल सेवा अनुभव' की पात्रता के उद्देश्य से ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले अपने सेवा के अनुभव को गिनने के हकदार हैं, जैसा कि 1976 के विनियमों की 'अनुसूची तकनीकी' के क्रम संख्या 2 के कॉलम संख्या 6 में दिया गया है?

3. क्या 1976 के विनियमों के अनुसार डिप्लोमा धारक परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) को 'एएमआईई' की योग्यता प्राप्त करने पर परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूची में उनकी ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख तक उपलब्ध डिग्री धारकों से नीचे रखा जाना चाहिए और क्या 1976 के विनियमों के अनुसार, परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक अलग वरिष्ठता सूची, अर्थात डिग्री और डिप्लोमा, बनाए रखने की आवश्यकता है?

13. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शोभा ने दलीलों का नेतृत्व किया। अपीलार्थियों का यह स्पष्ट रुख था कि प्रश्न सं.1 परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की तदर्थ/कार्यवाहक श्रेणी के खिलाफ निर्णय लिया गया था और उस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर अनंतिम हो गया है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्न संख्या 2 और 3 के संबंध में अपीलार्थियों के खिलाफ दिए गए निष्कर्षों पर गंभीरता से हमला किया है।

14. उच्च न्यायालय के अनुसार एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डिप्लोमा धारक इंजीनियरों को डिग्री धारकों की सूची में सबसे नीचे रखने और उन्हें केवल 3:7 के अनुपात में डिप्लोमा धारकों के रूप में सेवा में अपने अनुभव का लाभ देने की कथित प्रथा की पुष्टि करने वाला मंडल का संकल्प न तो पिछले अभ्यास द्वारा और न ही विनियमों द्वारा उचित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मंडल को दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ तैयार करने का निर्देश देने में गलती की। इस प्रकार खंड बेंच ने पुनर्विलोकन में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के प्रभाव को उलट कर और साथ ही डिप्लोमा धारक को एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पूरी पिछली सेवा का लाभ देकर अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर दिया।

15. अपीलार्थियों की ओर से उठाए गए दो मुख्य मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले, जैसा कि पहले देखा गया है, कुछ बाद के घटनाक्रमों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है जो विवाद में नहीं हैं। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के अनुसार मंडल ने 30.06.2007 को एक अस्थायी सामान्य वरिष्ठता सूची जारी की और 06.07.2007 को संकल्प दिनांक 17.04.1979 को वापस ले लिया। एक अंतिम सामान्य वरिष्ठता सूची 27.08.2007 को जारी की गई थी और अपीलार्थियों के अनुसार यह उनकी आपत्तियों को तय किए बिना तैयार की गई थी। परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर कई व्यक्तियों को अनंतिम पदोन्नति दी गई है जिन्होंने सेवा में रहते हुए एएमआईई परीक्षा उत्तीर्ण की और ऐसी पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त करने की तारीख के संबंध में कथित रूप से अपीलार्थियों से बहुत नीचे थे। वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं को इस न्यायालय में 25.09.2007 को या उसके तुरंत बाद प्राथमिकता दी गई थी। ऐसे ही एक मामले में ध्यान देना जारी करते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस बीच कोई बल पूर्वक कदम नहीं उठाए जाएंगे।

19.07.2010 को, परियोजना इंजीनियर (जूनियर) के 200 पदों को परियोजना इंजीनियर (सीनियर) के पद पर अपग्रेड किया गया और ऐसे 31 पदों को समाप्त कर दिया गया। उन्नयन के परिणामस्वरूप, 12.08.2010 को, परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर आसीन 168 व्यक्ति परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के उन्नत पद का अधिग्रहण करने के लिए आए।

16. अपीलार्थी के.के. दीक्षित और कुछ अन्य लोगों द्वारा वर्ष 1992 में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, तदर्थ पदोन्नति के खिलाफ उठाए गए वर्तमान विवाद के कारण, मंडल ने बाद में भी केवल तदर्थ पदोन्नति दी है और इसलिए कानून और विनियमों के अनुसार उन पदोन्नतियों को नियमित करने और रेजिडेंट इंजीनियर के अगले उच्च पद पर नियमित पदोन्नति करने के लिए विवाद का समाधान आवश्यक प्रतीत होता है। विचाराधीन मुद्दे केवल संबंधित नियतांश के खिलाफ पदोन्नति के लिए पात्रता से संबंधित हैं न कि वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए प्रावधान करने वाले विनियमों से।

17. उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न सं.3 से संबंधित मुद्दे में लिए गए निर्णय बहुत विवादास्पद नहीं हैं और इसलिए उन पर पहले विचार किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने का निर्देश दिया, एक डिग्री धारकों के लिए और दूसरी डिप्लोमा धारकों के लिए केवल मंडल के संकल्प दिनांक 17.04.1979 को प्रभावी बनाने की दृष्टि से यह पता लगाने के लिए आवश्यक अभ्यास किए बिना कि क्या प्रस्ताव विनियमों के अनुरूप था या विनियमों के साथ टकराव में था। इस तरह की कवायद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई थी जिसने संकल्प को मंजूरी नहीं दी और कहा कि यह विनियमों के विपरीत है। इसने यह भी सही देखा कि पहले की वरिष्ठता सूची केवल एक सामान्य वरिष्ठता सूची थी और किसी भी वरिष्ठता सूची की कोई पिछली प्रथा नहीं थी।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए प्रासंगिक तथ्यों पर विवाद नहीं किया। उच्च न्यायालय ने देखा कि अनुसूची तकनीकी और विनियम प्रोजेक्ट इंजीनियर (जूनियर) के पद के लिए भर्ती का केवल एक स्रोत प्रदान करते हैं जो कि सीधी भर्ती है और एक ही चयन प्रक्रिया डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों दोनों पर लागू होती है। और, इसलिए, केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता में अंतर के कारण विनियमों में इस उद्देश्य के लिए किसी प्रावधान के अभाव में उन्हें दो अलग-अलग संवर्गों से संबंधित नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक चैनल के लिए अलग-अलग नियतांश और अलग-अलग पात्रता मानदंड के कारण उन्हें अगली पदोन्नति के लिए दो चैनलों के रूप में माना जाना था।

19. अपीलार्थियों की ओर से, एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था कि विनियमों के खंड (9)(बी) में एक आदेश है कि प्रत्येक "श्रेणी के कर्मचारियों" के लिए वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और बनाए रखी जाएगी और इसलिए मंडल को डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों को इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए कर्मचारियों की अलग श्रेणी के रूप में मानना चाहिए। हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। विनियमों के संदर्भ में खंड (9)(बी) में उपयोग किए गए "कर्मचारियों की श्रेणी" शब्दों का अर्थ केवल कर्मचारियों द्वारा धारण किए गए पदों की श्रेणी हो सकता है। "श्रेणी" शब्द का उपयोग केवल विनियमों के खंड (6) में पदों के संदर्भ में किया गया है, हालांकि प्रतिनियुक्ति पर मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों के अवशोषण के मामले में खंड (9)(ए) जो अनुसूची तकनीकी के साथ पढ़ने पर पदोन्नति का प्रावधान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च पद पर पहली पदोन्नति, यानी परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पद से परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति के संबंध में, पात्र व्यक्ति की पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि परियोजना

अभियंता (कनिष्ठ) के संवर्ग को केवल वरिष्ठता के उद्देश्य से विभाजित नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के संवर्ग में पदोन्नति के लिए डिग्री धारकों के लिए 20 प्रतिशत और डिप्लोमा धारकों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के व्यावहारिक दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि मंडल वैध रूप से परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) धारक डिग्री और डिप्लोमा रखने वालों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार कर सकता है। इस तरह की पात्रता सूची को वरिष्ठता सूची के लिए गलत नहीं माना जा सकता है जो भर्ती के लिए चयन के समय मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर सामान्य होनी चाहिए। केवल अगर चयन प्रक्रिया अलग होती, तो अलग वरिष्ठता सूचियों के लिए बहस करने की कोई गुंजाइश हो सकती थी। प्रारंभिक चयन और नियमित नियुक्ति की तारीख के समय योग्यता के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रारंभिक वरिष्ठता में बदलाव के लिए किसी भी कानूनी शर्त की अनुपस्थिति में, वरिष्ठता सूची में केवल इसलिए बदलाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ डिप्लोमा धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) ने डिग्री के बराबर एएमआईई की योग्यता प्राप्त कर ली है। तीन साल या सात साल की सेवा का अनुभव क्रमशः डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों को केवल पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए हकदार बनाएगा ताकि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए विभिन्न नियतांश के प्रावधान को संतोषजनक ढंग से तैयार किया जा सके। इसलिए, हमें प्रश्न संख्या 3 के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

20. पक्षों के बीच आगे का विवाद प्रश्न संख्या 2 से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के संबंध में है। जिस प्राथमिक प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सेवा के दौरान एएमआईई की योग्यता प्राप्त करने वाले डिप्लोमा धारकों को डिग्री धारकों के लिए 20 प्रतिशत कोटे के मुकाबले परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद पर

पदोन्नति के लिए डिप्लोमा धारकों के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के अनुभव का लाभ दिया जाना चाहिए या उन्हें इस तरह के लाभ का लाभ उठाने के लिए एएमआईई की योग्यता प्राप्त करने के बाद सेवा का तीन साल का अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है।

21. ऊपर देखे गए मुद्दे के संदर्भ में, अपीलार्थी का रुख यह है कि डिग्री धारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा और डिप्लोमा धारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में गुणात्मक अंतर है और इसलिए, विनियमों में यह प्रावधान है कि डिग्री धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) तीन साल की सेवा के साथ और डिप्लोमा धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) सात साल की सेवा के साथ परियोजना इंजीनियर (सीनियर) के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। उनका आगे का मामला यह है कि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए नियतांश के रूप में क्रमशः 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत पद प्रदान करके, विनियमों ने दोनों वर्गों के लिए एक वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट बनाया है क्योंकि वे केवल अपने-अपने नियतांश में पदोन्नति के हकदार हैं। यह तथ्य कि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के दो अलग-अलग चैनलों के लिए पदोन्नति के लिए अलग नियतांश तय किया गया है, अपीलार्थियों के अनुसार, एक स्पष्ट संकेत है कि तीन साल की सेवा को डिग्री धारक के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त की जा सके जैसा कि एक डिप्लोमा धारक के मामले में है जो डिप्लोमा धारक के रूप में केवल सात साल की सेवा प्रदान करने पर पात्रता प्राप्त करता है। जब पदोन्नति का दावा एक निश्चित नियतांश के खिलाफ किया जाता है तो सेवा अनुभव की पात्रता मानदंड को अलग तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थियों का उपरोक्त रुख शैलेंद्र दानिया और अन्य बनाम एस.पी.दुबे और अन्य (2007) 5 एससीसी 535 के मामले में तीन न्यायाधिपतियों की पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर आधारित है। शैलेंद्र दानिया (ऊपर) के मामले में

निष्कर्षों को और समर्थन प्रदान करने के लिए, एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 पूरक (1) एससीसी 584; इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य अन्य एस. गोपालकृष्णन (2001) 2 एससीसी 362; चल्ला जया भास्कर और अन्य बनाम थुंगथुर्ती सुरेंद्र और अन्य (2010) 13 एससीसी 328; चंद्रवती पी. के. और अन्य बनाम सी. के. साजी और अन्य (2004) 3 एससीसी 734 और विजय सिंह देवड़ा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 3 एससीसी 118 के मामले में निर्णयों पर भी निर्भरता रखी गई है।

22. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले और डिप्लोमा धारकों, जिन्होंने बाद में सेवा में रहते हुए एएमआईई. की योग्यता प्राप्त की, के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने शैलेंद्र दानिया के मामले (उपरोक्त) के तथ्यों में अंतर करने का एक उत्साही प्रयास किया है। डिप्लोमा धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार शैलेंद्र दानिया के मामले में सेवा में प्रवेश के समय डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों की आवश्यक योग्यता में अंतर था। जबकि डिग्री धारक प्रवेश पद के लिए केवल अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ आवेदन करने के पात्र थे, डिप्लोमा धारकों के पास अतिरिक्त दो साल का अनुभव होना आवश्यक था और इसलिए दोनों को सेवा अनुभव के मामले में गुणात्मक रूप से अलग माना जाता था। दूसरे शब्दों में, निवेदन यह है कि शैलेंद्र दानिया के मामले में डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में गुणात्मक अंतर मुख्य रूप से उनके अलग-अलग जन्म चिन्ह होने के कारण था जो वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है। यह भी डिप्लोमा धारकों का मामला है कि पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले विनियमों में उपयोग किए गए शब्द वर्तमान मामले में अलग हैं क्योंकि खंड 'सेवा का अनुभव' से पहले 'कुल' शब्द का उपयोग किया गया है और इसलिए एक शाब्दिक व्याख्या पर, जैसा कि वर्तमान मामले में आवश्यक है, अपीलार्थी शैलेंद्र दानिया (उपरोक्त) के मामले

में निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुसूची तकनीकी में 'के साथ' शब्द पर भी बहुत जोर दिया गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि इसे 'और' के रूप में पढ़ा जाए जो तब संचयी पात्रता मानदंड को डिग्री के साथ सेवा के तीन साल के कुल अनुभव के रूप में पढ़ने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन केवल डिग्री और तीन साल के कुल सेवा अनुभव के रूप में। यह डिप्लोमा धारकों का मामला है कि 'कुल' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से न केवल डिग्री के साथ सेवा के अनुभव को बल्कि डिप्लोमा के साथ पहले से प्राप्त सेवा के अनुभव को भी गिनने के इरादे को इंगित करता है। श्री मनु मृदुल, कुछ प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, ने उपरोक्त दलीलों के समर्थन में अनिल कुमार गुप्ता और अन्य अन्य दिल्ली नगर निगम और अन्य (2000) 1 एससीसी 128; एम.बी. जोशी और अन्य आदि बनाम सतीश कुमार पांडे और अन्य आदि 1993 पूरक (2) एससीसी 419 और ए.के.रघुमनी सिंह और अन्य बनाम गोपाल चंद्र नाथ और अन्य (2000) 4 एससीसी 30 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। एक अपील में प्रत्यर्थियों के एक अन्य समूह की ओर से पेश होते हुए, श्री अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता ने रूप चंद अदलखा और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 1989 सप. (1) एससीसी 116 के मामले पर भरोसा किया।

23. श्री विजय हंसारिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, मंडल की ओर से उपस्थित हुए और डिप्लोमा धारकों के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि योग्यता के उद्देश्य से डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए क्रमशः तीन साल और सात साल का अलग-अलग सेवा अनुभव निर्धारित किया गया है, उनके अनुभव में किसी भी गुणात्मक अंतर पर नहीं बल्कि केवल शैक्षिक योग्यता में अंतर है। इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष मंडल का रुख जो उच्च न्यायालय के समक्ष उसके रुख के बिल्कुल विपरीत है, वह यह है कि एक डिप्लोमा धारक जिसके पास तीन साल का सेवा अनुभव है और जो एएमआईई की योग्यता प्राप्त करता है, वह तीन साल के अनुभव वाले डिग्री

धारकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति के लिए पात्रता का दावा करने के लिए विनियमों के तहत योग्य है। कुछ प्रोफार्मा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे प्रोफार्मा प्रतिवादी का मामला जो डिग्री धारक थे, अपीलार्थियों के समान है।

24. ऊपर उल्लिखित मुख्य मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को संबोधित करने से पहले, कुछ प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों को देखते हुए जैसे कि इन अपीलों में उत्पन्न होने वाला मुद्दा वरिष्ठता सूची में व्यक्तियों की वरिष्ठता की स्थिति से संबंधित है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय को न तो निर्णय लेने के लिए कहा गया था और न ही उसने वास्तव में परियोजना अभियंताओं (कनिष्ठ) या परियोजना अभियंताओं (वरिष्ठ) की अंतर वरिष्ठता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लिया था और इस न्यायालय को मंडल द्वारा प्रकाशित किसी भी वरिष्ठता सूची की शुद्धता में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, इन अपीलों में निर्धारण के लिए आने वाला मुख्य मुद्दा केवल इस बात से संबंधित है कि डिग्री धारक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्रता का दावा करने के उद्देश्य से डिप्लोमा धारक से डिग्री धारक बने परियोजना इंजीनियर (जूनियर) के सेवा अनुभव का क्या मूल्य, यदि कोई हो, दिया जाना है।

25. प्रारंभ में अपीलार्थियों की ओर से एक गंभीर विवाद उठाया गया था कि क्या अनुसूची तकनीकी में उल्लिखित परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव और योग्यता के संदर्भ में खंड 'सेवा का अनुभव' से पहले 'कुल' शब्द इस अनुसूची में एक अवैध प्रविष्टि है या क्या यह वास्तव में अनुसूची के मसौदे में मौजूद था जिसे मंडल और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। मंडल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे सामने मूल रिकॉर्ड रखे और

यह स्पष्ट किया कि संबंधित खंडों में 'कुल' शब्द अनुसूची तकनीकी के मूल मसौदे में मौजूद था जिसे विधिवत मंजूरी दी गई थी। मामला वहीं रुक गया है।

26. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर आते हुए, शैलेंद्र दानिया के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के संबंधित पैराग्राफ को प्रासंगिक तथ्यों के साथ संदर्भित करना उपयोगी होगा ताकि अपीलार्थियों के इस तर्क की सराहना की जा सके कि डिप्लोमा धारकों के लिए सेवा में प्रवेश करने के लिए दो साल के अनुभव के कारण जन्म चिन्ह की अनुपस्थिति में भी, जो उस मामले के तथ्यों के लिए विशिष्ट था, प्रासंगिक तथ्य और नियम की स्थिति भौतिक रूप से समान है और इसलिए उस मामले में निर्धारित कानून उसी तर्ज पर वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। शैलेंद्र दानिया के मामले में सहायक अभियंता के पद पर कुल रिक्तियों में से 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए नियम दिए गए थे और शेष को स्नातक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के लिए विशिष्ट नियतांश प्रदान करके पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। डिप्लोमा धारकों जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड आठ साल की योग्यता सेवा और स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए तीन साल की योग्यता सेवा थी। सहायक अभियंता के पद से आगे कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति हुई। इस पद के लिए, स्नातक इंजीनियरों के लिए न्यूनतम योग्यता अनुभव सहायक इंजीनियर के रूप में आठ वर्ष और डिप्लोमा धारकों के लिए सहायक इंजीनियर के ग्रेड में दस वर्ष था। हालांकि, पदानुक्रम में प्रारंभिक पद, यानी जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, चयन केवल सीधी भर्ती द्वारा से किया गया था और निर्धारित योग्यता "दो साल के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक" थी। लेकिन जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन करने में इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए कोई रोक नहीं थी और उन्हें किसी भी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं थी।

27. शैलेंद्र दानिया के मामले में इस न्यायालय ने एन. सुरेश नाथन (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर मजबूत भरोसा रखा और समझाया कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उस मामले का फैसला अनिवार्य रूप से नियम की व्याख्या पर किया और केवल विभाग में अपनाई गई पिछली प्रथा से उस व्याख्या का समर्थन पाया। एन. सुरेश नाथन (ऊपर) में, शामिल प्रश्न शैलेंद्र दानिया (ऊपर) और वर्तमान मामले के समान था। प्रासंगिक नियम जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रदान किया गया था, जिसमें दो श्रेणियां शामिल थीं, अर्थात् ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ डिग्री धारक जूनियर इंजीनियरों में से एक और ग्रेड में छह साल की सेवा के साथ डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियरों में से एक। वहाँ, प्रत्येक श्रेणी से 50 प्रतिशत नियतांश था। न्यायालय ने पूरी योजना के आलोक में नियम की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष निकाला कि तीन साल की अवधि केवल डिग्री प्राप्त करने की तारीख से शुरू हो सकती है न कि पहले। डिग्री प्राप्त करने से पहले डिप्लोमा धारक के रूप में ग्रेड में सेवा को डिग्री धारक के रूप में तीन साल की सेवा के उद्देश्य से डिग्री के साथ ग्रेड में सेवा के रूप में नहीं गिना जा सकता है। एन. सुरेश नाथन के मामले (उपरोक्त) में फैसले को समझाने और उसका पालन करने के अलावा, शैलेंद्र दानिया के मामले (उपरोक्त) में फैसले में तथ्यों और नियमों में अंतर के आधार पर कुछ बाद के फैसलों पर भी विचार किया गया और अलग किया गया जैसे कि एम. बी. जोशी (उपर्युक्त) के मामले में; डी. स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 4 एससीसी 753; अनिल कुमार गुप्ता (ऊपर) और ए. के. रघुमनी (ऊपर)।

28. शैलेंद्र दानिया (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में फैसले पर भी ध्यान दिया, जिस पर अपीलार्थियों ने भी भरोसा किया है। इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैरा 5 में कहा गया है कि "जब योग्यता के अलावा, अनुभव निर्धारित किया जाता है, तो

इसका मतलब केवल आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त करना होगा, न कि ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस मामले में विशिष्ट सामान्य जानकारी/निर्देश था कि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के बाद अनुभव की गणना की जाएगी। इस मुद्दे को और विस्तार देने के बजाय शैलेंद्र दानिया (ऊपर) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 43 से 45 को निकालना उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैंः

> "43. प्रासंगिक नियमों की पूरी योजना को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि डिप्लोमा धारक अपने नियतांश में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उनके पास आठ साल की सेवा न हो, जबकि स्नातक अभियंताओं के पास अपनी डिग्री के अलावा तीन साल का सेवा अनुभव होना आवश्यक होगा। यदि नियमों का प्रभाव और इरादा डिप्लोमा को उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से डिग्री के बराबर मानने के लिए था, तो दो अलग-अलग चैनलों से कनिष्ठ अभियंता के कैडर में शामिल होने पर बिना डिप्लोमा धारकों को दो साल की सेवा की आगे की योग्यता की किसी भी आवश्यकता के अधीन समान विचार करने की आवश्यकता होगी। कनिष्ठ अभियंता के पद पर सेवा में शामिल होने के समय, इंजीनियरिंग में डिग्री बिना किसी पूर्व अनुभव के पर्याप्त योग्यता है, जबकि डिप्लोमा धारकों को सेवा में शामिल होने के लिए अपने डिप्लोमा के अलावा दो साल का अनुभव होना चाहिए। सेवा नियमों के अनुसार, सहायक अभियंता के पद पर कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, जबकि पदोन्नति के लिए विशिष्ट नियतांश स्नातक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ

अभियंता के लिए निर्धारित किया गया है। जब नियमों के तहत नियतांश निर्धारित किया जाता है, तो स्नातक कनिष्ठ अभियंता की उच्च पद पर पदोन्नति 25 प्रतिशत नियतांश तक सीमित होती है। जहाँ तक डिप्लोमा धारकों का संबंध है, उच्च पद पर उनकी पदोन्नति 25 प्रतिशत तक सीमित है। एक पात्रता मानदंड के रूप में, एक डिग्री को कनिष्ठ अभियंता के लिए तीन साल की सेवा द्वारा योग्य बनाया जाता है, जबकि डिप्लोमा धारकों के लिए आठ साल की सेवा की आवश्यकता होती है। तीन साल के सेवा अनुभव के साथ डिग्री और आठ साल के सेवा अनुभव के साथ डिप्लोमा ही डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियर के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा में गुणात्मक अंतर को दर्शाता है। स्नातक कनिष्ठ अभियंता के रूप में तीन साल का सेवा अनुभव और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के रूप में आठ साल का सेवा अनुभव, जो पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड है, प्रदान की गई सेवा की विभिन्न गुणवत्ता का संकेत है। दिए गए मामले में, क्या यह कहा जा सकता है कि एक डिप्लोमा धारक जिसने अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान डिग्री प्राप्त की है, उसने अभियंता के रूप में अनुभव केवल इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि उसने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। यह कहने के बराबर होगा कि डिप्लोमा धारक के रूप में अपनी सेवा में उनके द्वारा प्राप्त अनुभव गुणात्मक रूप से एक स्नातक अभियंता के अनुभव के समान है। नियम ने विशेष रूप से एक स्नातक कनिष्ठ अभियंता और एक डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के रूप में प्रदान की गई सेवा में अंतर किया। डिग्री धारक अभियंता के अनुभव को डिप्लोमा धारक के अनुभव के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। डिग्री धारकों

और डिप्लोमा धारकों के अनुभव के बीच का अंतर नियमों के तहत कार्यकारी अभियंता के पद पर आगे की पदोन्नति में भी बनाए रखा जाता है, जिसमें डिग्री धारकों या डिप्लोमा धारकों को कोई अलग नियतांश नहीं दिया जाता है और पदोन्नति सहायक अभियंता के संवर्ग से की जानी है। नियम डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग सेवा अनुभव प्रदान करते हैं। आठ साल का सेवा अनुभव रखने वाले डिग्री धारक सहायक अभियंता कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जबकि डिप्लोमा धारक सहायक अभियंता को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए सहायक अभियंता के पद पर दस साल का सेवा अनुभव होना आवश्यक होगा। यह इंगित करता है कि नियम स्वयं डिग्री धारकों के लिए आठ साल की योग्यता सेवा और डिप्लोमा धारकों के लिए दस साल के सेवा अनुभव में अंतर करता है। नियम अपने आप में एक ही पद पर प्रदान की जाने वाली सेवा में गुणात्मक अंतर लाता है। यह एक स्नातक अभियंता और डिप्लोमा धारक अभियंता द्वारा एक ही पद पर सेवा के गुणात्मक अंतर का स्पष्ट संकेत है। हमें ऐसा लगता है कि पदोन्नति के लिए एक आवश्यक मानदंड के रूप में योग्यता से जुड़ी सेवा की अलग-अलग अवधि सेवा में प्रशासनिक हित पर आधारित है। डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के लिए उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की विभिन्न अवधि अभियंता द्वारा संचालित पद के लिए अनुकूल है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्च तकनीकी ज्ञान प्रशासनिक दक्षता और गुणवत्ता उत्पादन को बेहतर बढ़ावा देगा। तकनीकी विशिष्ट कार्य को अधिक कुशलता से करने के लिए उच्च तकनीकी ज्ञान की

आवश्यकता होगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता व्यापक परिप्रेक्ष्य विकसित करती है और इसलिए अधिक योग्य व्यक्ति द्वारा एक ही पद पर प्रदान की जाने वाली सेवा गुणात्मक रूप से अलग होगी।

44. प्रासंगिक नियमों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता के सीमित नियतांश में डिग्री धारक द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अनुभव को डिप्लोमा धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा के बराबर नहीं माना जा सकता है और न ही डिग्री धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जब एक निश्चित नियतांश से दावा किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए आवश्यक शर्त का पालन करना पड़ता है। 25 प्रतिशत विशिष्ट नियतांश तीन साल के अनुभव वाले डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए तय किया गया है। इस प्रकार, एक साधारण अध्ययन पर, इस प्रकार आवश्यक अनुभव एक डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता के रूप में होगा। नियम के तहत पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत नियतांश तीन साल के अनुभव वाले डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंताओं को सौंपा गया है, जबकि डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए उनके 25 प्रतिशत नियतांश में आठ साल का अनुभव आवश्यक है। स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित संबंधित नियतांश में पदोन्नति के लिए योग्यता प्रदान करने के रूप में सेवा के वर्षों की संख्या के साथ शैक्षिक योग्यता को मान्यता दी गई थी। स्नातक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए जलरोधक डिब्बे हैं। वे अपने-अपने

नियतांश में पदोन्नति के हकदार हैं। न तो डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारकों के नियतांश में पदोन्नति का दावा कर सकता है क्योंकि उसने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है और न ही डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए निर्धारित पदोन्नति कोटे के लिए कोई दावा कर सकता है। डिग्री-धारकों और डिप्लोमा-धारकों के विभिन्न चैनलों से पदोन्नति के लिए अलग-अलग नियतांश का निर्धारण स्वयं इंगित करता है कि पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा डिग्री या डिप्लोमा के साथ एक आवश्यक पात्रता मानदंड है, जो वर्तमान मामले में डिग्री-धारक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा है। सेवा के विशेष वर्ष निर्दिष्ट कोटे के भीतर पदोन्नति के अवसर के लिए प्रदान की जाने वाली कुछ शैक्षिक योग्यता के साथ संचयी आवश्यकता होने के कारण, डिग्री धारक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है, न कि डिप्लोमा धारक के रूप में। पात्रता मानदंड के रूप में सेवा अनुभव को किसी अन्य चीज के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह नियतांश विशेष रूप से डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए बनाया गया है।

45. एक आवश्यक परिणाम के रूप में, हमारा विचार है कि डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता जिन्होंने सेवा के कार्यकाल के दौरान इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, उन्हें डिग्री प्राप्त करने के बाद पद पर तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी ताकि वे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बन सकें, यदि वे डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से पदोन्नति का दावा करते हैं, तो सहायक अभियंता के

पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक कनिष्ठ अभियंता और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के लिए नियतांश निर्धारित किया गया है।"

29. प्रतिवादीओं की ओर से कनिष्ठ अभियंता के पद पर सेवा में शामिल होने के समय योग्यता में अंतर जैसा कि पैराग्राफ 43 में दर्शाया गया है, वर्तमान मामले को इस आधार पर अलग करने के लिए उजागर किया गया था कि परियोजना इंजीनियर कनिष्ठ पद पर सेवा में शामिल होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि डिप्लोमा धारकों को अपने डिप्लोमा के अलावा दो साल का अनुभव होना चाहिए। शाब्दिक रूप से, यह अंतर मान्य है, लेकिन हमारे विचार में पैराग्राफ 43 में जिन अन्य विचारों पर चर्चा की गई थी, उनका बहुत अधिक महत्व है, विशेष रूप से स्नातक परियोजना अभियंता (जूनियर) और डिप्लोमा धारक परियोजना अभियंता (जूनियर) के लिए निर्धारित विशिष्ट नियतांश है। वर्तमान मामले में भी, एक पात्रता मानदंड के रूप में, एक डिग्री को आगे तीन साल की सेवा द्वारा योग्य बनाया जाता है, जबकि एक डिप्लोमा को आगे सात साल की सेवा द्वारा योग्य बनाया जाता है। ये भेद सेवा में शामिल होने के समय जन्म चिन्ह की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान मामले में इस तरह के जन्म चिन्ह की अभाव भौतिक नहीं है। शैलेंद्र दानिया (उपरोक्त) के मामले में इस तरह का जन्म चिन्ह केवल एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध था, लेकिन हमारे विचार में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई भौतिक अंतर नहीं होगा कि तीन साल के सेवा अनुभव के साथ डिग्री और सात साल के सेवा अनुभव के साथ डिप्लोमा अपने आप में एक डिग्री धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा और एक डिप्लोमा धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा में गुणात्मक अंतर को इंगित करता है।

30. जैसा कि शैलेंद्र दानिया के मामले (उपरोक्त) के पैराग्राफ 36 में कहा गया है, हमें नियमों की पूरी योजना, प्रासंगिक समय पर तथ्यों और परिस्थितियों और प्रश्न में बुलाए गए नियमों के आधार पर मामले का फैसला करने की आवश्यकता है, ताकि

स्वतंत्र रूप से शब्दों, शामिल सिद्धांत और पिछले अभ्यास, यदि कोई हो, को अर्थ दिया जा सके। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, "तीन साल की सेवा" या "सात साल की सेवा" शब्दों से पहले आने वाले "के साथ" शब्द को एक स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है और 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के संबंधित नियतांश के साथ पदोन्नति के लिए दोनों वर्गों के लिए बनाए गए दो पानी से भरे डिब्बों के आलोक में, यह माना जाना चाहिए कि तीन साल की सेवा का कुल अनुभव डिग्री धारक के रूप में सेवा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को विनियमों में प्रावधान द्वारा मजबूत किया गया है कि इसी तरह की पदोन्नति के लिए एक डिप्लोमा धारक को सात साल का कुल सेवा अनुभव होना चाहिए। संबंधित विनियमन एक डिप्लोमा धारक के लिए पदोन्नति के लिए किसी भी कम कुल अनुभव पर विचार नहीं करता है जो सेवा में रहते हुए डिग्री या एएमआईई योग्यता प्राप्त कर सकता है। ऐसी उच्च योग्यता प्राप्त करने पर भी संबंधित डिप्लोमा धारक को न तो अन्य डिप्लोमा धारकों की तुलना में कोई लाभ दिया जाता है और न ही उसे डिप्लोमा धारकों के लिए प्रदान किए गए 30 प्रतिशत नियतांश के खिलाफ विचार के अधिकार से बाहर आदेश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में तीन साल के सेवा अनुभव वाले डिग्री धारकों के लिए 20 प्रतिशत नियतांश के जलरोधक डिब्बे में प्रवेश करने के लिए, एएमआईई योग्यता वाले डिप्लोमा धारक को यह दिखाना होगा कि वह पूरी पात्रता मानदंड को पूरा करता है, यानी वह डिग्री धारक के रूप में सेवा का तीन साल का अनुभव रखने वाला डिग्री धारक है। इस तरह के जलरोधक डिब्बे और अलग नियतांश को अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता है ताकि डिग्री धारकों की पदोन्नति की संभावना को प्रभावित करने के लिए उस श्रेणी में एक डिप्लोमा धारक को शामिल किया जा सके जिसके पास डिग्री धारक के रूप में सेवा का तीन साल का अनुभव नहीं है। विनियमों में इस तरह के किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, ऐसी स्थिति में किसी भी समानता की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि सात साल के सेवा अनुभव वाला डिप्लोमा धारक भी डिप्लोमा

धारकों के लिए 30 प्रतिशत नियतांश के मुकाबले केवल पदोन्नति की संभावना या अवसर तक ही सीमित है।

31. जहाँ तक 'सेवा के अनुभव' शब्दों से पहले आने वाले 'कुल' शब्द का संबंध है, सेवा से संबंधित परिस्थितियों और पिछले इतिहास से, इसे नियमित क्षमता में प्रदान की जाने वाली सेवा के साथ-साथ तदर्थ या कार्यवाहक या अस्थायी आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। 'कुल' शब्द का अर्थ डिप्लोमा धारक या डिग्री धारक के रूप में प्रदान की गई सेवा नहीं माना जा सकता है। यदि यह इरादा होता, तो 'कुल' शब्द को केवल डिग्री धारकों की सेवा के तीन साल के कुल अनुभव के संदर्भ में शामिल किया जाता, न कि डिप्लोमा धारकों के रूप में सेवा के सात साल के अनुभव के संदर्भ में। किसी भी मामले में डिप्लोमा धारक को पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए सात साल का सेवा अनुभव होना आवश्यक है और इसलिए उपरोक्त संदर्भ में 'कुल' शब्द निरर्थक या अनावश्यक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट किया है और कहा है कि नियमित करने से पहले तदर्थ या कार्यवाहक आधार पर प्रदान की गई सेवा को पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए नहीं गिना जा सकता है और यह पहलू अब विवाद के दायरे में नहीं है। इसलिए सुसंगत विनियम में 'के साथ' या 'कुल' शब्द के उपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता है और शैलेंद्र दानिया (उपरोक्त) के मामले में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू होता है, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया था।

32. चल्ला जया भास्कर (ऊपर); चंद्रवती पी. के. (ऊपर) और विजय सिंह देवड़ा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के अन्य निर्णय भी उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जो हमने शैलेंद्र दानिया के मामले (ऊपर) के आधार पर लिया है। चल्ला जया भास्कर (ऊपर) के मामले में फैसले के पैरा 29 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने एन. सुरेश नाथन के मामले (ऊपर) और शैलेंद्र दानिया के

मामले (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों का पालन किया। चंद्रवती पी. के. (उपरोक्त) के मामले में एएमआईई योग्यता प्राप्त करने पर डिप्लोमा धारकों की श्रेणी से डिग्री धारकों की श्रेणी में विकल्प के प्रयोग द्वारा स्थानांतरण के लिए नियम लागू थे। उस संदर्भ में, पैराग्राफ 30 में इस न्यायालय ने कहा कि डिप्लोमा धारक अधिकारी सेवा के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने पर डिग्री धारकों के नियतांश या डिप्लोमा धारकों के नियतांश से पदोन्नति का विकल्प चुन सकता है, लेकिन एक बार जब वह डिग्री धारकों के नियतांश में पदोन्नति का विकल्प चुनता है, तो वरिष्ठता का नियम लागू होगा क्योंकि उसने बाद में उसके लिए योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा और उनके मामले पर तभी विचार किया जा सकता है जब ऐसी डिग्री योग्यता रखने वालों की पदोन्नति के मामलों पर विचार किया जाए। विजय सिंह देवड़ा (उपरोक्त) के मामले में नियम की स्थिति अलग थी, लेकिन पैराग्राफ 9 में इस न्यायालय ने योग्यता के उद्देश्यों के लिए डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता के रूप में प्रदान की गई सेवा की केवल सीमित मान्यता की अनुमति दी और इस आधार पर अनुमत प्रक्रिया को उचित ठहराया कि यह तीनों समूहों के साथ न्याय करेगा (जैसा कि उस मामले में मौजूद था) और कोई भी दूसरे पर कूद नहीं पाएगा और अवैध रूप से दूसरे के वैध अधिकार पर चढ़ाई नहीं करेगा, " अन्यथा, वास्तव में योग्य स्नातकों को नीचे की ओर धकेल दिया जाएगा और योग्यता प्राप्त करने पर अयोग्य देर से प्रवेश करने वाले योग्य लोगों से आगे निकल जाएंगे।"

33. प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर ऊपर ध्यान दिया गया है। शैलेंद्र दानिया (ऊपर) के मामले में उन सभी मामलों पर ध्यान दिया गया और उन्हें अलग किया गया या समझाया गया और हम पाते हैं कि उनमें से कोई भी मामला प्रतिवादी के लिए कोई मददगार नहीं है। उन मामलों में, या तो कोई वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट नहीं था और विभिन्न श्रेणियों के लिए निश्चित नियतांश था या केवल

प्रारंभिक भर्ती से संबंधित विज्ञापन और नियम या प्रतियोगिता केवल डिप्लोमा धारकों के दो समूहों के बीच थी। रूप चंद अदलखा (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय वास्तव में अपीलार्थियों के मामले में मदद करता है क्योंकि उस मामले में इस न्यायालय ने कहा था कि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों को पदोन्नति के लिए पात्रता प्रदान करने के लिए अलग-अलग सेवा अनुभव निर्धारित किया जा सकता है और शैक्षिक योग्यता के आधार पर ऐसा वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनुमेय है।

34. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हम इन अपीलों में योग्यता पाते हैं और तदनुसार उन्हें प्रश्न संख्या 2 के संबंध में उच्च न्यायालय के विचारों को उलटने की अनुमति दी जाती है। जैसा कि खण्ड पीठ ने अपील के तहत सामान्य निर्णय में उल्लेख किया है। हमारा मानना है कि डिप्लोमा के आधार पर भर्ती किए गए परियोजना इंजीनियर (जूनियर), 'एएमआईई' की योग्यता प्राप्त करने पर, डिग्री धारक परियोजना इंजीनियर (जूनियर) की पदोन्नति के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत नियतांश के मुकाबले परियोजना इंजीनियर (सीनियर) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से ऐसी योग्यता प्राप्त करने से पहले अपने सेवा के अनुभव को गिनने के हकदार नहीं हैं। ऐसे 20 प्रतिशत नियतांश के खिलाफ पदोन्नति का दावा करने के लिए एएमआईई की योग्यता या डिग्री प्राप्त करने के बाद तीन साल का सेवा अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए।

35. हम मंडल और उसके अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं को हमारे उपरोक्त विचारों के आलोक में निस्तारित करें और रिट याचिकाओं में उठाए गए विवादों का निर्धारण करने के लिए पात्र व्यक्तियों को तेजी से और अधिमानतः 4 महीने के भीतर राहत प्रदान करें, उन लेनदेनों को बाधित किए बिना जो पहले हुए थे और जिन्हें रिट याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। दूसरे

शब्दों में, 1992 से पहले की गई नियमित पदोन्नति, जो 1992 में दायर रिट याचिकाओं का विषय नहीं थी, इस फैसले में व्यक्त किए गए विचारों के कारण फिर से नहीं खोली जाएगी।

36. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****